to affect primarily the agriculture in India ; and

(c) if so, whether government has taken a note of the recommendations made by the institute and Policy formulations made in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI S. KRISHNA KUMAR) : (a) and (b) Yes, Sir.

(c) The Government of India does not share this pessimistic observation. Persistent efforts are being made to increase production of foodgrains to meet the needs of our growing population.

**Area under Soyabean Cultivation**

3319. SHRI RAJENDRA PRASAD MODI : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to State :

(a) the areas where Soyabean is grown ;

(b) the total Soyabean produced during the year 1992-93 ;

(c) whether Government propose to expand the area under Soyabean cultivation ; and

(d) if so, the steps taken in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI S. KRISHNA KUMAR) : (a) The major soyabean growing States are Madhya Pradesh, Maharashtra. Rajasthan and Karnataka.

(b) The total production of Soyabean during 1992-93 was 31.06 lakh tonnes.

(c) and (d) Yes, Sir. Under the Oilseed Production Programme assistance is given for seed production and distribution, Plant Protection chemical equipments, improved farm implements, rhyzobium culture etc. to the soyabean farmers in various soyabean growing states.

**अच्छी किस्म के बीजों की अनुपलब्धता**

**3320. श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसानों को अच्छी किस्म के बीज नहीं मिलते हैं और यदि उन्हें बीज मिल भी जाते हैं तो वे समय पर नहीं मिलते हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्या-क्या कदम उठा रही है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०कृष्ण कुमार)** : (क) और (ख) किसानों को बीजों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना मुख्यतया राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है जो अपने राज्य बीज निगमों, कृषि उद्योग संगठनों आदि के माध्यम से उत्पादन आयोजित करती है। तथापि राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय एजेंसियां जैसे राष्ट्रीय बीज निगम, भारतीय राज्य फार्म निगम भी स्वयं अपनी अवसंरचना के माध्यम से बीजों का उत्पादन और वितरण कर रही हैं। भारत सरकार प्रत्येक बोआई मौसम अर्थात् खरीफ और रबी से पहले क्षेत्रीय बीज समीक्षा बैठकों का आयोजन करती है ताकि अलग-अलग राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की बीज की जरूरत और उपलब्धता के बारे में अनुमान लगाया जा सके और यह राज्य सरकारों/सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के बीज संगठनों की अधिसूचित किस्मों/संकर किस्मों आदि के प्रजनक बीजों का आबंटन भी करती है। वर्ष 1992-93 और 1993-94 के लिए बीजों की मांग और उपलब्धता की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है (नीचे देखिए)। भारत सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से एक राष्ट्रीय बीज परियोजना भी शुरु की है ताकि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में बीज उद्योग में बुनियादी ढांचे संबंधी सुविधाओं, उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी सुविधाओं में सुधार किया जा सके। नई बीज नीति (1988) में विश्व में कहीं भी उपलब्ध उच्च गुणवत्ता वाले बीजों तक हमारे किसानों की पहुंच सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।